GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 19 March, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	'विकास का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्राथमिकता'
Page 03 **Syllabus : GS 1: Art and Culture**	तेलंगाना में मुदुमल के खड़े पत्थर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल
Page 04 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या लोकपाल के पास संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर अधिकार है
Page 05 **Syllabus : Prelims Fact**	स्वतंत्र भाषण सर्वेक्षण में भारत 24वें स्थान पर
In News	अभ्यास वरुण
Page 11 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं?

GEO IAS It's about quality

Page 03 : GS 2 : Indian Polity

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और मद्रास उच्च न्यायालय के अलग-अलग निर्णयों को खारिज कर दिया है, जिसमें ऑरोविले में विकास गतिविधियों को रोक दिया गया था।

- फैसले में पर्यावरण संरक्षण और विकास के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, दोनों को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है।

फैसले की मुख्य बातें:

- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:**

  o जबकि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संरक्षित है, औद्योगीकरण के माध्यम से *विकास का अधिकार* भी अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

  o सतत विकास को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच एक सुनहरा संतुलन बनाना चाहिए।

- **एनजीटी के 2022 के आदेश को खारिज करना:**

  o एनजीटी, चेन्नई ने पर्यावरण मंजूरी की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए ऑरोविले की टाउनशिप परियोजना को रोक दिया था।

  o सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एनजीटी ने विकास को रोकने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।

- **मास्टर प्लान की स्वीकृति:**

  o ऑरोविले मास्टर प्लान को ऑरोविले फाउंडेशन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2001 में मंजूरी दी थी, जिसे बाद में 2010 में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

  o सुप्रीम कोर्ट ने योजना को बरकरार रखा और कहा कि विकास कानूनी रूप से स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए।

- **वन संरक्षण तर्क:**

  o विपक्ष ने तर्क दिया कि सड़क निर्माण से दरकाली जंगल नष्ट हो जाएगा।

  o ऑरोविले फाउंडेशन ने इसका विरोध किया कि यह एक मानव निर्मित वृक्षारोपण है, न कि प्राकृतिक वन, और इसलिए इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

- **भविष्य की विकास परियोजनाओं पर प्रभाव:**

- यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि यदि विकास परियोजनाएं कानूनी रूपरेखा का पालन करती हैं तो उन्हें मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता।

- हालांकि, सतत विकास महत्वपूर्ण बना हुआ है - परियोजनाओं को आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

निष्कर्ष

- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। जबकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए, विकास परियोजनाओं को मनमाने अवरोधों का सामना नहीं करना चाहिए यदि वे कानूनी ढांचे का अनुपालन करते हैं। यह निर्णय भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: विकास का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दोनों ही भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार हैं। ऑरोविले पर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में चर्चा करें कि सतत विकास किस तरह इन अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। (250 words)

GEO IAS
It's about quality

तेलंगाना के नारायणपेट में मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इस स्थल के ऐतिहासिक और खगोलीय महत्व को उजागर करते हुए भारत सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा था।

Standing stones of Mudumal in Telangana on tentative list of UNESCO World Heritage Sites

Serish Nanisetti
HYDERABAD

The *menhirs* or the standing stones of Mudumal in Narayanpet in Telangana have made it to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites. The application was forwarded by the Centre to the world body.

Mudumal, on the banks of the Krishna that separates the State from Karnataka, has been a well-known *menhir* site.

"Nearly 1,200 large sized stones standing vertically map the skies as it existed 3,000 years ago. From them, we know the date and positions of the constellations of Leo, Ursa Major, Ursa Minor, Virgo, Taurus etc.," says conservation architect Surya Narayan Murthy who helped prepare the application for the Mudumal site in collaboration with DAM and Deccan Heritage Academy Trust.

The *menhirs* in Mudumal in Narayanpet of Telangana.

समाचार की मुख्य बातें

मुदुमल मेनहिर के बारे में

- कृष्णा नदी के तट पर तेलंगाना के मुदुमल में स्थित है।
- मेगालिथिक काल से लगभग **3,000** वर्ष पुराना होने का अनुमान है।
- लगभग **1,200** बड़े, लंबवत खड़े पत्थर सिंह, उरसा मेजर, उरसा माइनर, कन्या और वृषभ जैसे खगोलीय नक्षत्रों के साथ संरेखित हैं।
- संभवतः समय और अनुष्ठानों के लिए प्राचीन खगोलीय मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है।

यूनेस्को की संभावित सूची और इसका महत्व

- अस्थायी सूची में शामिल स्थल विश्व धरोहर की स्थिति के लिए संभावित उम्मीदवार हैं।
- समावेश से वैश्विक मान्यता, संरक्षण निधि और पर्यटन क्षमता में वृद्धि होती है।

पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व

- मेनहिर मेगालिथिक संरचनाएं हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर दफनाने, अनुष्ठानों या खगोलीय अवलोकनों के लिए किया जाता है।
- ब्रिटेन (स्टोनहेंज), फ्रांस और कर्नाटक (ब्रह्मगिरी मेगालिथ) में भी इसी तरह के स्थल मौजूद हैं।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: तेलंगाना के मुदुमल मेनहिर के विशेष संदर्भ में भारत में महापाषाण स्थलों के महत्व पर चर्चा करें। ऐसे स्थल प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और खगोलीय ज्ञान की हमारी समझ में किस प्रकार योगदान करते हैं? (250 words)

GEO IAS
It's about quality

सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांच करने का निर्णय लिया है कि क्या भारत के शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर अधिकार क्षेत्र है।

Supreme Court to consider if Lokpal has powers over judges of constitutional courts

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

A Bench of the Supreme Court's senior-most judges headed by Justice B.R. Gavai on Tuesday decided to examine in detail if judges of constitutional courts come within the jurisdiction of the country's top ombudsman, Lokpal, as public functionaries including the Prime Minister, Union Ministers, Members of Parliament and Union government officials.

"We will consider the issue of the jurisdiction of the Lokpal," Justice Gavai addressed the courtroom.

The court was hearing a *suo motu* case initiated after Lokpal, through a January 27 order, assumed jurisdiction to investigate complaints against serving High Court judges. The

ombudsman classified High Court judges as public servants who came within the ambit of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 same as Government Ministers and officials.

The Special Bench had stayed the Lokpal order on February 20, terming it "very disturbing" with a potential to impact the independence of the judiciary.

Appearing on Tuesday before the Special Bench also comprising Justices Surya Kant and A.S. Oka, Solicitor-General Tushar Mehta said the "limited question" was whether judges of constitutional courts were indeed public servants under the Lokpal Act.

Senior advocate Kapil Sibal, assisting the court, said he wanted to go a "little further" to urge the Bench to examine if criminal complaints against judges could be registered in police stations.

"Can a complaint be ever filed outside the remit of a constitutional authority. That is the fundamental issue. Can someone go to a police station and register a first information report (FIR)?" he submitted.

However, Mr. Mehta objected to extending the ambit of the *suo motu* case. He insisted the Bench should confine its present line of inquiry to whether the judges of constitutional courts were public servants under Section 14 of the Lokpal Act.

The top law officer contended that the Constitution Bench had already, in a majority judgment in the *K. Veeraswami* case of 1991, settled the question of whether the police could register an FIR against a sitting High Court or Supreme Court judge.

The Lokpal has effectively bypassed long Constitutional and procedural formalities by directly assuming jurisdiction to investigate High Court judges.

In its January 27 order, the Lokpal had found the argument that a High Court judge was outside the ombudsman's jurisdiction "too naive".

It concluded that a High Court judge came well within the ambit of clause (f) of Section 14(1) of the 2013 Act.

Clause (f) of Section 14 notes the Lokpal has jurisdiction over "any person who is or has been a chairperson or member or officer or employee in any body or Board or corporation or authority or company or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established by an Act of Parliament or wholly or partly financed by the Central government or controlled by it".

The Lokpal interpreted the term 'any person' in the clause to include a judge of a High Court.

- यह मुद्दा तब उठा जब लोकपाल ने 27 जनवरी के आदेश में उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगा दी और इसे "बहुत परेशान करने वाला" बताया क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

मामले में मुख्य मुद्दे

- **न्यायाधीशों पर लोकपाल का अधिकार क्षेत्र**
  - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लोकपाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों जैसे सार्वजनिक पदाधिकारियों की जांच करने का अधिकार देता है।

- o सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकपाल अधिनियम की धारा 14(1)(एफ) के तहत लोक सेवकों की श्रेणी में आते हैं।
- o लोकपाल का तर्क है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस धारा के अंतर्गत आते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में चिंता जताई है।

- **न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव**
  - o यदि लोकपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच कर सकता है, तो इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण में समझौता हो सकता है।
  - o न्यायिक जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत महाभियोग प्रक्रिया जैसे संवैधानिक तंत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **के. वीरस्वामी मामले (1991) का संदर्भ**
  - o के. वीरस्वामी मामले में संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी मौजूदा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी (**FIR**) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति से ही दर्ज की जा सकती है।
  - o सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि इस मिसाल को बरकरार रखा जाना चाहिए, ताकि संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बिना किसी भी प्रत्यक्ष पुलिस कार्रवाई या लोकपाल के हस्तक्षेप को रोका जा सके।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की संवैधानिक वैधता की जाँच करें। न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए न्यायिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? (250 words)

GEO IAS
It's about quality

स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में, मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को 24वां स्थान दिया गया है।

India takes 24th spot in free speech survey

The Hindu Bureau
NEW DELHI

A new global survey by the Future of Free Speech, an independent U.S.-based think tank, has ranked India 24th out of the 33 countries surveyed on the question of support for free speech. Its report, titled 'Who in the world supports free speech?' states that "while abstract support for free speech remains strong, commitment to protecting controversial speech is eroding in many parts of the world."

The survey, conducted in October 2024, also revealed that "more countries have seen declines rather than improvements in free speech support since 2021, with some of the biggest drops occurring in democratic nations like the United States, Israel, and Japan".

Scandinavia dominated the top rankings, with Norway and Denmark finishing at the apex of the Future of the Free Speech Index with scores of 87.9 and 87.0.

Disconnect flagged

Indonesia (56.8), Malaysia (55.4), and Pakistan (57.0) showed the biggest improvements, though they remained at the lower end of the ranking. India, with a score of 62.6, was placed 24th, between South Africa (66.9) and Lebanon (61.8). At the same time, some authoritarian-leaning nations – such as Hungary (85.5) and Venezuela (81.8) – scored high, "suggesting a disconnect between government restrictions and public attitudes".

As regards its findings concerning India, the survey found that while a majority of Indians consider it very important to speak freely without government censorship, support for criticism of government policies was below the global average.

For instance, 37% of Indian respondents supported the statement that "governments should be able to prevent people" from criticising government policies – the highest percentage among all the countries surveyed.

Public sentiment

In contrast, 5% of the respondents supported this statement in the U.K., while only 3% endorsed this sentiment in Denmark.

In general, nations that are more supportive of free speech tend to enjoy more freedom of expression in practice and vice versa. But India was an exception to this pattern. "The most substantial disconnects from the general pattern are represented by India, Hungary, and Venezuela where the actual protection of free speech is very low compared to the popular support. These are all cases of democratic backsliding in countries that previously demonstrated high levels of respect for political liberties, including freedom of expression," the report stated.

When asked whether their ability to speak freely about political matters has improved or worsened over the past year, "Indians and South Africans believe that they have undergone the most significant progress, although observers and rankings tend to agree that the situation in India has become worse, if anything," the report noted.

- "दुनिया में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है?" शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक स्तर पर मुक्त भाषण के लिए अमूर्त समर्थन मजबूत बना हुआ है, लेकिन विवादास्पद भाषण की रक्षा करने की प्रतिबद्धता कम हो रही है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

वैश्विक रुझान

- संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और जापान जैसे देशों में 2021 से मुक्त भाषण के समर्थन में गिरावट देखी गई।
- नॉर्वे और डेनमार्क क्रमशः 87.9 और 87.0 के स्कोर के साथ रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं।
- इंडोनेशिया (56.8), मलेशिया (55.4), और पाकिस्तान (57.0) ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया, लेकिन निचले स्तर पर रहे।

भारत की स्थिति

- भारत 62.6 के स्कोर के साथ 24वें स्थान पर है, जो दक्षिण अफ्रीका (66.9) और लेबनान (61.8) के बीच है।
- अधिकांश भारतीय मुक्त भाषण को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन सरकारी नीतियों की आलोचना के लिए समर्थन वैश्विक औसत से कम है।
- 37% भारतीय उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि सरकार के पास अपनी नीतियों की आलोचना को रोकने की शक्ति होनी चाहिए - सभी सर्वेक्षण किए गए देशों में सबसे अधिक।

जनमत और सरकारी नीतियों के बीच विसंगति

- हंगरी (85.5) और वेनेजुएला (81.8) जैसे कुछ सत्तावादी झुकाव वाले देशों ने उच्च स्कोर किया, जो सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक दृष्टिकोणों के बीच विसंगति को दर्शाता है।
- सर्वेक्षण में भारत, हंगरी और वेनेजुएला को लोकतांत्रिक पतन के प्रमुख उदाहरणों के रूप में उल्लेख किया गया है, जहाँ मुक्त भाषण के लिए जनता का समर्थन मजबूत है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा कमजोर है।

भारत में धारणा बनाम वास्तविकता

- कई भारतीयों का मानना है कि उनकी स्वतंत्र रूप से बोलने की क्षमता में सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक रैंकिंग और पर्यवेक्षक इसके विपरीत सुझाव देते हैं - कि भारत में मुक्त भाषण सुरक्षा खराब हो गई है।.

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स में सर्वोच्च स्थान पर है?

a) संयुक्त राज्य अमेरिका

b) नॉर्वे

c) भारत

d) जापान

उत्तर: (b) **नॉर्वे**

In News : Exercise Varuna

- भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं अपने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, वरुण 2025 के 23वें संस्करण के लिए तैयारी कर रही हैं।

अभ्यास वरुण के बारे में

- यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है।
- **1993** में शुरू किए गए इस अभ्यास को **2001** में 'वरुण' नाम दिया गया और यह भारत-फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है।
- वरुण **2025** अभ्यास का **23**वां संस्करण है और यह अरब सागर में होगा।
- इसमें उच्च तीव्रता वाले नौसैनिक अभ्यासों की एक श्रृंखला दिखाई जाएगी, जिसमें उप-सतह, सतह और हवाई क्षेत्रों में संयुक्त संचालन पर जोर दिया जाएगा।
- भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत, **INS** विक्रांत और फ्रांसीसी विमानवाहक पोत, चार्ल्स डी गॉल अपने लड़ाकू विमानों, विध्वंसक, फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ भाग लेंगे, जो दोनों नौसेना बलों की संयुक्त ताकत और परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

- अभ्यास का एक मुख्य आकर्षण फ्रांसीसी राफेल-एम और भारतीय मिग-**29K** लड़ाकू जेट के बीच उन्नत वायु रक्षा अभ्यास और नकली हवा से हवा में युद्ध परिदृश्य होंगे।
- इन अभ्यासों का उद्देश्य सामरिक समन्वय को बढ़ाना और युद्ध की तत्परता को परिष्कृत करना है।
- इसके अतिरिक्त, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास पानी के भीतर डोमेन जागरूकता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि सतह युद्ध संचालन दोनों नौसेनाओं की समन्वित संलग्नता और युद्धाभ्यास को अंजाम देने की क्षमता का परीक्षण करेंगे।

GEO IAS
It's about quality

What factors influence women's political participation?

While discussions on women's participation often highlight the social and cultural biases that hinder their electoral success, less attention is given to how everyday women engage with the electoral process

Rebecca Rose Varghese

Deshpande R., 'Shaping of the Woman Constituency in Indian Elections: Evidence from the NES Data', Studies in Indian Politics, Vol 12 Issue No. 2, 303-317, November 16, 2024

The participation of women in Indian politics has been a subject of extensive discourse among scholars, especially given the paradox that while India has produced several influential women leaders, overall political engagement among women remains poor. Unlike many countries where the gender gap in political participation began narrowing in the 1990s, India saw this shift only in the 2010s.

While discussions on women's participation often highlight the social and cultural biases that hinder their electoral success, less attention is given to how everyday women engage with the electoral process when opportunities arise. Their voting patterns, choices, and agency in shaping election outcomes remain under-explored. And, though political parties and women's movements frequently celebrate women voters during elections, this recognition often treats them as a homogenous group, overlooking the intersections of caste, class, religion, and region that shape their political behaviour. Women's support for Donald Trump in the 2016 U.S. elections, and their participation in the riots of the 1990s in India illustrate how women's political engagement is far more complex and requires in-depth understanding.

It is within this context that Rajeshwari Deshpande's study, 'Shaping of the Woman Constituency in Indian Elections: Evidence from the NES Data', becomes significant. Her analysis of National Election Studies (NES) data sheds light on the increasing voter turnout among women and their growing participation in the political sphere. By examining how women vote and whether their choices are influenced primarily by gender or by other social identities, her research provides a nuanced understanding of the evolving role of women in Indian elections. Her findings help to understand whether we are closer to shaping a women's constituency in Indian elections. This study offers critical insights into the gendered dimensions of Indian elections, highlighting key patterns, contradictions, and challenges in women's political agency and its broader socio-political implications.

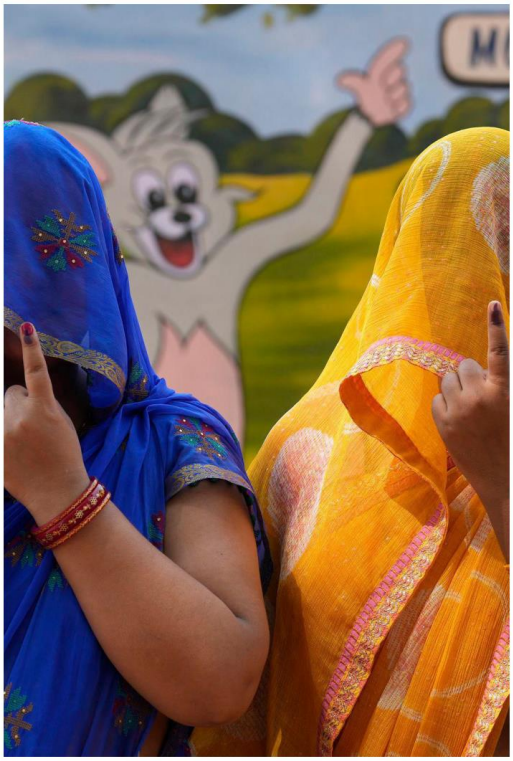

Women voters after casting their vote in the Lok Sabha elections in Prayagraj, on May 25, 2024. AP

Mere beneficiaries or active agents?

As mentioned earlier, it was only in 2010 that there was a significant increase in the share of women who voted; and all political parties sought to capitalise on this shift by introducing policies and schemes specifically targeting women. However, these policies often frame women as passive beneficiaries rather than political agents. Welfare programs like Ujjwala and the Pradhan Mantri Awas Yojana were pivotal to the Bharatiya Janata Party's (BJP) victory in the 2019 Lok Sabha elections, while schemes like 'Ladli Behna' and 'Ladli Laxmi' were credited for the party's success in Madhya Pradesh. These initiatives reinforce the notion of women as dependents, with political leaders positioned as benevolent providers rather than recognising women as autonomous decision-makers.

Deshpande argues that high voter turnout does not necessarily translate to real political power. For years, women were considered marginal participants in politics, with efforts made to carve out a 'non-political' political constituency for them. Despite their growing presence at the polls, political parties and media continue to frame their votes as driven by welfare benefits. Analysing NES data helps assess whether the rise in women voters signals real political agency or mere surface-level inclusion.

Beyond voting

While the increasing turnout of women voters in the 2024 Lok Sabha elections is noteworthy, voting is not the only form of political participation. Participation in rallies, campaigns, political affiliations, and policy advocacy also indicates political involvement. In these areas, women still lag behind men. Only 14% of women report seeking advice from their spouses on voting decisions – indicating growing agency –but this remains significantly higher than men's. This suggests that despite increased voter participation, deeper political engagement faces social and structural barriers.

One explanation scholars offer for the increased turnout of women is the self-empowerment hypothesis, which suggests that rising literacy rates and employment opportunities have empowered women to vote independently. Efforts by the Election Commission to ensure women's voter registration could also be attributed to the increased turnout.

However, the author challenges this explanation, pointing out two critical contradictions: women's overall workforce participation remains low, weakening the argument that economic independence is driving higher turnout. Additionally, the proportion of registered female voters compared to male voters remains imbalanced, indicating that fewer women are being registered.

An alternative explanation for the increased women voter turnout could be the large-scale male migration of men contributing to higher turnout among women in States traditionally considered socially and economically 'backward'.

These trends highlight that while turnout has increased, broader political participation remains limited.

Other identities

Women's voting behaviour in India is not driven solely by gender identity but is also deeply shaped by regional, caste, and class dynamics. The NES data highlight that State-specific political and social contexts significantly influence electoral choices, undermining the idea of a unified, pan-Indian women's voting bloc. Instead, women's voting preferences are molded within the broader framework of their community identities.

State-level variations demonstrate this complexity. For instance, in States such as Tamil Nadu, Kerala, and West Bengal, where electoral politics have historically been shaped by strong regional parties, women's preferences are often aligned with regional political movements rather than national gender-based voting trends. Caste and class divisions further complicate this narrative. The BJP's voter base has traditionally been skewed toward urban, upper-class, and upper-caste groups, while Congress has drawn more support from the urban poor and marginalised communities. However, this alignment is also not absolute – many women, particularly from lower socioeconomic backgrounds, continue to vote based on the interests of their communities rather than on a broader gender-based agenda.

Women's support for different parties

NES data indicate that Congress has historically maintained a gender advantage, consistently receiving more female support than male. This trend continued in 2024, except in 2014, when the party suffered a nationwide decline. Left parties also had a gender advantage, but their declining influence has diminished this effect on the national stage. The BJP, in contrast, has faced a gender disadvantage, with fewer women voting for the party compared to men. However, this gap has been narrowing. Previously, the gender gap in BJP support exceeded 20%, whereas in 2024, it reduced to approximately 7%. The BJP's targeted outreach to women has contributed to this shift, though much of its support still comes only from welfare beneficiaries. Even within this group, men support the BJP more than women.

Region-specific variations further complicate women's support for the BJP. In some non-BJP-ruled States, more women than men voted for the party, despite a lack of increased female voter turnout. Conversely, in other States, women showed a stronger preference for opposition parties, creating an uneven gender gap. This suggests that while the BJP has made inroads among female voters, gender alone does not define women's electoral choices – other intersecting identities and political contexts remain crucial.

The data from past elections highlight three key trends in women's political participation in India. First, while women's voter turnout has steadily increased, their overall political engagement beyond voting remains lower than men's. Second, women's voting patterns and political involvement are not just shaped by gender identity; factors such as caste, class, and regional influences also play a significant role. Third, despite targeted outreach, the BJP has historically faced a gender disadvantage, with more men than women supporting the party. These developments indicate that we are still far from the formation of a distinct women's constituency in Indian politics, as their electoral choices remain intertwined with broader socio-political factors.

Rebecca Rose Varghese is a freelance journalist.

GS Paper 02 **भारतीय राजनीति**

UPSC Mains Practice Question: **भारत में महिलाओं की बढ़ती मतदाता भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि वे अधिक राजनीतिक एजेंसी बन गई हैं।" मतदान के अलावा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।**

संदर्भ:

- भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी व्यापक चर्चा का विषय रही है, खास तौर पर इस विरोधाभास को देखते हुए कि कई प्रभावशाली महिला नेताओं की मौजूदगी के बावजूद, महिलाओं के बीच कुल मिलाकर राजनीतिक भागीदारी कम है। जहाँ कई देशों में 1990 के दशक में राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक अंतर कम होता देखा गया, वहीं भारत में यह बदलाव 2010 के दशक में ही देखने को मिला।
- महिलाओं की भागीदारी पर मुख्य रूप से ध्यान उन सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर रहा है जो उनकी चुनावी सफलता में बाधा डालते हैं, लेकिन इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि आम महिलाएँ चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से भाग लेती हैं।
- राजेश्वरी देशपांडे का अध्ययन,'भारतीय चुनावों में महिला निर्वाचन क्षेत्र का आकार: एनईएस डेटा से साक्ष्य', महिलाओं के मतदान पैटर्न, उनकी पसंद पर प्रभाव और चुनाव परिणामों को आकार देने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

- **मतदाता मतदान और चुनावी भागीदारी**
  - 2010 के बाद महिलाओं के मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे राजनीतिक दलों को उन्हें लक्षित करने वाली नीतियां पेश करने के लिए प्रेरित किया गया। हालाँकि, इस बढ़ी हुई भागीदारी ने वास्तविक राजनीतिक शक्ति में तब्दील नहीं किया है। राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को उनके विकल्पों को आकार देने में जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र के अंतर को पहचानने के बजाय एक समरूप मतदाता समूह के रूप में देखते हैं।

- **कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका**
  - महिलाओं को अक्सर सक्रिय निर्णय लेने वालों के बजाय निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में पेश किया जाता है। कल्याणकारी योजनाएँ जैसे:
    - उज्ज्वला योजना (महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन)
    - प्रधानमंत्री आवास योजना (महिला लाभार्थियों के लिए आवास)

- लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजनाएँ (मध्य प्रदेश में वित्तीय सहायता)
  - ये योजनाएँ 2019 और क्षेत्रीय चुनावों में भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे महिलाओं के स्वतंत्र मतदाता होने के बजाय राजनीतिक नेताओं को प्रदाता के रूप में देखने की धारणा को बल मिलता है।

मतदान से परे: राजनीतिक गतिविधियों में कम भागीदारी

- राजनीतिक भागीदारी मतदान से परे है और इसमें रैलियों और अभियानों में भाग लेना, राजनीतिक पार्टी की सदस्य बनना और नीतिगत बदलावों की वकालत करना शामिल है।
- इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। केवल 14 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनसाथी से मतदान संबंधी सलाह लेने की बात कही है, जो निर्णय लेने में कुछ हद तक स्वायत्तता का संकेत देता है, लेकिन यह अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है।

स्व-सशक्तिकरण परिकल्पना: मिथक या वास्तविकता?

o कुछ विद्वानों का तर्क है कि बढ़ती साक्षरता दर और रोजगार के अवसरों ने महिलाओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने में सक्षम बनाया है। हालाँकि, दो विरोधाभास इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं:

· महिलाओं की कार्यबल भागीदारी कम बनी हुई है, जिससे यह तर्क कमजोर पड़ता है कि आर्थिक स्वतंत्रता अधिक मतदान का कारण है।

· पंजीकृत महिला मतदाताओं का अनुपात अभी भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में कम है, जो दर्शाता है कि कई महिलाओं को अभी भी मतदाता सूची से बाहर रखा जा रहा है।

पुरुष प्रवास का प्रभाव

o शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पुरुषों के प्रवास ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में महिला मतदाताओं के मतदान में वृद्धि में योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीछे रह गई महिलाओं ने मतदान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसका राज्य-स्तरीय चुनावी नतीजों पर प्रभाव पड़ा है।

महिलाओं के मतदान व्यवहार में जाति, वर्ग और क्षेत्र की भूमिका

o महिलाओं का मतदान व्यवहार केवल लिंग पहचान से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि जाति और वर्ग की गतिशीलता, क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों और धार्मिक और सामुदायिक जुड़ावों से भी गहराई से प्रभावित होता है।

राज्य-स्तरीय विविधताएँ महिलाओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करती हैं:

o तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में, महिलाएँ राष्ट्रीय लिंग-आधारित रुझानों की तुलना में क्षेत्रीय दलों के साथ अधिक जुड़ती हैं।

o उच्च जाति और शहरी महिलाओं द्वारा भाजपा का समर्थन करने की अधिक संभावना है, जबकि हाशिए पर पड़े समुदाय कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की ओर झुकते हैं।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में प्रमुख रुझान

- वर्ष 2010 से मतदान में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन व्यापक राजनीतिक भागीदारी कम बनी हुई है।
- मतदान पैटर्न केवल लिंग के बजाय जाति, वर्ग और क्षेत्रीय प्रभावों सहित कई पहचानों द्वारा आकार लेते हैं।

- भाजपा को ऐतिहासिक रूप से लैंगिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन लक्षित कल्याण नीतियों ने महिला मतदाताओं के बीच इसकी स्थिति में सुधार किया है।
- भारतीय राजनीति में महिलाओं का कोई एकीकृत निर्वाचन क्षेत्र नहीं है; चुनावी विकल्प सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारकों से जुड़े हुए हैं।

GEO IAS
It's about quality